



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012026-269083  
CG-DL-E-03012026-269083

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 381।

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 2025/पौष 10, 1947

No. 381।

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 2025/PAUSAH 10, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2025

मामला सं. - एडी (ओआई) - 52/2025

विषय: चीन पीआर में उत्पन्न या वहां से निर्यातित "नायलॉन 6 चिप्स और 3 से कम सापेक्ष चिपचिपाहट (आरवी) के साथ कणिकाओं के आयात के संबंध में एंटी-डंपिंग जांच की शुरुआत।

- फा. सं. 6/60/2025-डीजीटीआर—समय-समय पर संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सीमा शुल्क टैरिफ (क्षति के निर्धारण के लिए डंप किए गए लेखों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रह) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया था (इसके बाद "नियम" या "एंटी-डंपिंग नियम" के रूप में संदर्भित), मैसर्स गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" के रूप में भी जाना जाता है) ने नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकारी" के रूप में संदर्भित) के समक्ष "नायलॉन 6 चिप्स और दानेदार पदार्थ जिनकी सापेक्ष श्यानता (आरवी) 3 से कम है" (जिसे आगे "विषय वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी" कहा गया है) के आयात से संबंधित डंपिंग-विरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है, जो चीन गणराज्य और रूस (जिसे आगे "विषय देश" कहा गया है) से उत्पन्न या निर्यात किए जाते हैं।

- आवेदक ने आरोप लगाया है कि विषय देश से संबंधित वस्तुओं के डंप किए गए आयात से भौतिक क्षति हो रही है

और उसने संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

#### क. विचाराधीन उत्पाद

- वर्तमान अनुप्रयोग में विचाराधीन उत्पाद नायलॉन 6 (पॉलियामाइड 6) चिप्स और कणिकाओं के साथ सापेक्ष चिपचिपाहट (आरवी) 3 से नीचे है।
- विचाराधीन उत्पाद मुख्य रूप से कपड़ा अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन ऑटोमोटिव और इलेक्ट्रिकल उद्योगों जैसे हल्के-ज्यूटी गैर-कपड़ा अनुप्रयोगों के लिए भी उपयुक्त हो सकता है।

#### बहिष्करण

- पाउडर के रूप में उत्पाद को विशेष रूप से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

#### माप की इकाई

- विचाराधीन उत्पाद के लिए माप की निर्धारित इकाई मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (किलोग्राम) है।

#### टैरिफ वर्गीकरण

- विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत उप-शीर्षक 3908 10 11 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, आवेदक ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन उत्पाद को कोड 3908 10 19, 3908 10 21, 3908 10 39, 3908 10 41, 3908 10 49, 3908 10 79 और 3908 90 00 के तहत भी आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
- वर्तमान जांच के पक्षकार पीयूसी के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं और जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) पद्धति, यदि कोई हो, का प्रस्ताव कर सकते हैं।

#### ख. समान वस्तु

- आवेदक ने कहा है कि आवेदक द्वारा उत्पादित और विषय देश से निर्यात की गई वस्तु में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक द्वारा उत्पादित लेख और जो विषय देश से आयात किया गया है, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, मूल्य निर्धारण, वितरण और विपणन, और विषय वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। विषय सामान और आवेदक द्वारा निर्मित लेख तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। आवेदक ने दावा किया है कि विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ता विषय वस्तुओं और आवेदक द्वारा निर्मित वस्तु का परस्पर उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार, वर्तमान जांच शुरू करने के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित वस्तु को प्रथम दृष्टया विषय देश से आयात किए जा रहे उत्पाद के लिए वस्तु के समान माना जाता है।

#### ग. विषय देश

- वर्तमान जांच में विषय देश चीन पीआर और रूस है।

#### घ. जांच की अवधि (पीओआई)

- प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 (12 महीने) तक की अवधि को जांच की अवधि (पीओआई) के रूप में माना है (इसके बाद "पीओआई" के रूप में संदर्भित)। क्षति की जांच अवधि पिछले तीन वित्तीय वर्षों, यानी 2021-22, 2022-23, 2023-24 और पीओआई को कवर करेगी।

#### ङ. घरेलू उद्योग और स्थिति

- यह आवेदन मेसर्स गुजरात पॉलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने विषय देशों से विषय वस्तुओं का आयात नहीं किया है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने संबंधित देशों से उक्त वस्तुओं का आयात नहीं किया है और संबंधित देशों के उत्पादकों या निर्यातकों से उनका कोई संबंध नहीं है। आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि वे एकमात्र घरेलू उत्पादक हैं और भारत में उक्त वस्तुओं के कुल उत्पादन का 100% हिस्सा उन्हीं का है। अतः, आवेदक प्रथम दृष्टया एडीडी नियम, 1995 के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की श्रेणी में आता है और आवेदन एडीडी नियम, 1995 के नियम 5(3) की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

### च. कथित डंपिंग का आधार

#### क. चीन के लिए सामान्य मूल्य

13. आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक । के नियम-7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 8(2) का हवाला दिया है और कहा है कि चीनी उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए कि नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 8(3) के अनुसार विषय वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। आवेदक ने दावा किया है कि चीन पीआर के लिए, सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक । के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।

14. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि तीसरे देश में बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य या निर्मित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने के प्रयास किए गए थे। हालांकि, आवेदक को बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या लागत के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। इसलिए, आवेदक ने आवेदक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसमें मार्जिन के लिए उचित वृद्धि की गई है।

#### ख. रूस के लिए सामान्य मान

15. आवेदक ने दावा किया है कि रूस में तुलनीय घरेलू कीमतें ऐसी जानकारी की गोपनीय प्रकृति के कारण उपलब्ध नहीं थीं; इसलिए, कैप्रोलैक्टम के निर्यात-आधारित मूल्यों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विद्युत शुल्कों, अनुमानित विनिर्माण और रूपांतरण लागत, बिक्री के लिए उपयुक्त परिवर्धन, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और उचित लाभ सहित यथोचित रूप से उपलब्ध सूचना का उपयोग करके उत्पादन की लागत का निर्माण करके वैकल्पिक आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया था।

16. हालांकि, प्राधिकारी ने आरंभ करने के उद्देश्य से सामान्य मूल्य पर विचार किया है, जिसका निर्माण भारत में उत्पादन लागत के आधार पर किया गया है, जिसमें बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्यय तथा दोनों विषय देशों के लाभ के लिए उचित अतिरिक्त राशि शामिल है।

#### ग. निर्यात मूल्य

17. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात मूल्य डीजी सिस्टम डेटा में दी गई सूचना के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ मूल्य पर विचार करके निर्धारित किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक प्रभार, पत्तन व्यय आदि के लिए समायोजन का दावा किया गया है।

#### घ. डंपिंग मार्जिन

18. सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य की तुलना कारखाना-पूर्व स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि पाठन माजन न्यूनतम स्तर से ऊपर है और संबंधित देशों से निर्यात किए जाने वाले विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्टया इस बात के प्रमाण हैं कि संबंधित देश से विचाराधीन उत्पाद को संबंधित देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में डंप किया जा रहा है।

#### ड. क्षति और कारण लिंक

19. आवेदक ने डंप किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान किए हैं। विषय देश से विषय आयात की मात्रा में निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों शब्दों में वृद्धि हुई है। आयात के कारण मूल्य में कमी और मंदी के प्रमाण हैं। विषय आयात का घरेलू उद्योग के लाभप्रदता मापदंडों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

20. उपर्युक्त से, प्राधिकारी को प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विषयगत देशों में मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के पाठन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा कथित पाठन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं, जो नियमों के नियम 5 के अनुसार पाठनरोधी जांच आरंभ करने, कथित पाठन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाठनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए उचित हैं, जो यदि लगाया जाए तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

#### क. डंपिंग रोधी जांच की शुरुआत

21. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर और विषय देश में उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद की डंपिंग के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर संतुष्टि प्राप्त

करने के बाद, विचाराधीन उत्पाद के कथित डंपिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति और ऐसी क्षति और डंप किए गए आयात के बीच कारण संबंध, और एडी नियमों के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9ए के अनुसार, प्राधिकारी, एतद्वारा, विषय देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विचाराधीन उत्पाद के संबंध में डंपिंग के अस्तित्व, डिग्री और प्रभाव को निर्धारित करने और एंटी-डंपिंग शुल्क की उचित राशि की सिफारिश करने के लिए एक एंटी-डंपिंग जांच शुरू करता है। जो यदि लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

**ख. प्रक्रिया**

22. इस जांच में एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

**छ. जानकारी प्रस्तुत करना**

23. सभी इच्छुक पक्षों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए सभी संचार और प्रस्तुतियाँ उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तुतियाँ का विवरण खोज योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में और डेटा फाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हों।

24. संबंधित देशों में ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबंधित देशों की सरकार, और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं, जिन्हें विचाराधीन उत्पाद से जुड़े होने के लिए जाना जाता है, को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस आरंभ अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी दर्ज कर सकें। ऐसी सभी जानकारी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से दर्ज की जानी चाहिए।

25. कोई अन्य इच्छुक पक्ष भी इस दीक्षा अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक प्रस्तुतीकरण कर सकता है, जैसा कि ऊपर पैरा (23) में उल्लिखित है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति देने वाले किसी भी पक्ष को अन्य इच्छुक पार्टियों को इसका गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराना आवश्यक है।

27. इच्छुक पार्टियों को इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) और सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित रूप से नजर रखने की सलाह दी जाती है। इच्छुक पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से डीजीटीआर (<https://www.dgtr.gov.in/>) की वेबसाइट पर जाएं ताकि वे विषय की जांच में आगे के घटनाक्रमों से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचनाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिसों के बारे में सूचित रहें।

**ज. अंतिम तिथि**

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी के तहत सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक सबमिशन के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी) को संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में उस तारीख से 37 दिनों के भीतर अपलोड किया जाना चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण प्राधिकारी द्वारा परिचालित किया जाएगा या एडी नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा, 1995। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।

29. सभी इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) को सूचित करें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपनी प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दाखिल करें।

30. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणी दर्ज करने के लिए 15 दिन की अवधि इस दीक्षा अधिसूचना के ऊपर पैरा 28 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।

31. पीयूसी/पीसीएन के संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकारी, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है, जो पहले प्रस्तावित नहीं था या दीक्षा अधिसूचना से अलग है, तो समय का विस्तार 15 दिनों तक बढ़ाया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित समय का 15 दिन का विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं होता है। 15-दिन के विस्तार (यदि दी गई हो) से परे समय के और विस्तार के अनुरोधों पर आमतौर पर असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जाएगा, एडी नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप।

32. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा SETU पोर्टल के माध्यम से ऊपर पैराग्राफ 28 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद सबमिट किए गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

33. **गोपनीय आधार पर जानकारी प्रस्तुत करना**

34. जहां वर्तमान जांच का कोई पक्ष गोपनीय प्रस्तुतियाँ करता है या प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर जानकारी प्रदान करता है, ऐसे पक्ष को नियमों के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी प्रासंगिक व्यापार नोटिसों के अनुसार ऐसी जानकारी का एक गैर-गोपनीय संस्करण एक साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकृत हो सकती हैं।

35. प्रश्नावली के उत्तरों सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई भी प्रस्तुतीकरण (परिशिष्ट/अनुलग्न सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

36. इस तरह के सबमिशन को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर 'गोपनीय' या 'गैर-गोपनीय' के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना चाहिए। इस तरह के चिह्नों के बिना प्राधिकारी को किए गए किसी भी सबमिशन को प्राधिकारी द्वारा 'गैर-गोपनीय' जानकारी के रूप में माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य इच्छुक पार्टियों को इस तरह के प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होगा।

37. गोपनीय संस्करण में वह सभी जानकारी शामिल होगी जो स्वभाव से, गोपनीय और/या अन्य जानकारी है, जो ऐसी जानकारी के आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। उस जानकारी के लिए जो प्रकृति से गोपनीय होने का दावा किया जाता है, या वह जानकारी जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, जानकारी के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई जानकारी के साथ एक अच्छा कारण विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी जानकारी का खुलासा क्यों नहीं किया जा सकता है।

38. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर की गई जानकारी का गैर-गोपनीय संस्करण गोपनीय जानकारी के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना आवश्यक है, अधिमानतः अनुक्रमित या खाली (जहां इंडेक्सेशन संभव नहीं है) और ऐसी जानकारी को उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो उस जानकारी पर निर्भर करती है जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है। गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी के सार की उचित समझ की अनुमति देने के लिए गैर-गोपनीय सारांश पर्याप्त विवरण में होना चाहिए। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करने वाली पार्टी यह संकेत दे सकती है कि ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और पर्याप्त और पर्याप्त स्पष्टीकरण वाले कारणों का एक व्यापार जिसमें इस तरह का सारांश संभव क्यों नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।

39. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रकृति की जांच करने पर गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि प्राधिकारी संतुष्ट है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध की आवश्यकता नहीं है या यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता या तो जानकारी को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटीकरण को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।

40. इसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और पर्याप्त कारण विवरण के बिना किया गया कोई भी सबमिशन, और गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिस को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

**ज. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण**

41. किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय संस्करण अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से सुलभ होंगे।

**ट. असहयोग**

42. यदि कोई इच्छुक पक्ष इस आरंभिक अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित उचित अवधि के भीतर या निर्धारित समय के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार करता है और अन्यथा आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे इच्छुक पक्ष को गैर-सहयोगी घोषित कर सकता है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड कर सकता है और केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जो वह उचित समझे।

अमिताभ कुमार, नामित प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Directorate General of Trade Remedies)**

**INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st December, 2025

**Case No. AD(OI) – 52/2025**

**Subject: Initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Nylon 6 Chips and Granules with relative viscosity (RV) below 3” originating in or exported from China PR and Russia.**

1. **F. No. 6/60/2025-DGTR**—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping duty on Dumped Articles for Determination of Injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter referred to as the “Rules” or the “Anti-dumping Rules”), M/s. Gujarat Polyfilms Private Limited (hereinafter also referred to as the “applicant” ) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”), for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Nylon 6 Chips and Granules with relative viscosity (RV) below 3” (hereinafter referred to as “subject goods” or “product under consideration” or “PUC”), originating in or exported from China PR and Russia (hereinafter referred to as “subject countries”).
2. The applicant has alleged that dumped imports of the subject goods from the subject countries is causing material injury and has requested the imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject countries.

**A. PRODUCT UNDER CONSIDERATION**

3. The product under consideration in the present application is “Nylon 6 (Polyamide 6) Chips and Granules with relative viscosity (RV) below 3.”
4. The product under consideration is primarily used for textile applications but may also be suitable for light-duty non-textile applications such as automotive and electrical industries.

**Exclusion**

5. The product in powder form is specifically excluded from the scope of product under consideration.

**Unit of measurement**

6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tons (MT) or Kilogram (Kg).

**Tariff classification**

7. The product under consideration is classified under Chapter 39 of the Customs Tariff Act under the sub-headings 3908 10 11. However, the applicant has alleged that the product under consideration is also imported under the code 3908 10 19, 3908 10 21, 3908 10 39, 3908 10 41, 3908 10 49, 3908 10 79, and 3908 90 00. The customs classification is indicative only and not binding on the scope of the product under consideration.
8. The parties to the present investigation may provide their comments on the scope of PUC and propose product control numbers (PCN) methodology, if any, within 15 days of circulation of the receipt of intimation of

initiation of the investigation.

#### **B. LIKE ARTICLE**

9. The applicant has stated that there are no significant differences in the article produced by the applicant and exported from the subject countries. The article produced by the applicant and that imported from the subject countries is comparable in terms of physical and chemical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing, and tariff classification of the subject goods. The subject goods and the article manufactured by the applicant are technically and commercially substitutable. The applicant has claimed that the consumers of the product under consideration are using the subject goods and the article manufactured by the applicant interchangeably. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the article produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

#### **C. SUBJECT COUNTRIES**

10. The subject countries in the present investigation are **China PR and Russia**.

#### **D. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)**

11. The Authority has considered the period from **1<sup>st</sup> July 2024 to 30<sup>th</sup> June 2025** (12 months) as the period of investigation (POI) for the present investigation (hereinafter referred to as "POI"). The injury investigation period shall cover the period 1<sup>st</sup> April 2021 to 31<sup>st</sup> March 2022, 1<sup>st</sup> April 2022 to 31<sup>st</sup> March 2023, 1<sup>st</sup> April 2023 to 30<sup>th</sup> June 2024 and the period of investigation.

#### **E. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

12. The application has been filed by M/s. Gujarat Polyfilms Private Limited. The applicant has submitted that they have not imported the subject goods from the subject countries and is not related to producers and exporter from the subject countries. The applicant has submitted that they are the sole domestic producer and accounts for 100% of the total production of the subject goods in India. Therefore, the applicant *prima facie* satisfies the standing and constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the ADD Rules, 1995 and the application satisfies the requirements of Rule 5(3) of the AD Rules, 1995.

#### **F. BASIS OF ALLEGED DUMPING**

##### **a. Normal Value for China**

13. The applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of Rule- 7 of Annexure I of the Rules. The applicant has cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms of Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed that for China PR, normal value should be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules.

14. The applicant has submitted that efforts were made to determine normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country. However, the applicant could not get reliable information regarding the information on price or cost in market economy third country. Therefore, applicant has determined the normal value based on price payable in India, based on cost of production, along with selling, general and administrative expenses and reasonable profits.

##### **b. Normal Value for Russia**

15. The applicant has claimed that comparable domestic prices in Russia were not available due to the confidential nature of such information; therefore, the normal value was determined on an alternative basis by constructing the cost of production using reasonably available information, including export-based prices of caprolactam, publicly available power tariffs, estimated manufacturing and conversion costs, with appropriate additions for selling, general and administrative expenses and reasonable profit.

16. However, the Authority for the purpose of initiation has considered the normal value which has been constructed on the basis of the cost of production in India, with reasonable addition for selling, general & administrative expenses, and profits for both the subject countries.

##### **c. Export Price**

17. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port expenses and bank charges.

**d. Dumping Margin**

18. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject countries. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject countries is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject countries.

**G. INJURY AND CAUSAL LINK**

19. The applicant has provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject countries has increased in both absolute as well as relative terms. There is evidence of price suppression and depression due to imports. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.

20. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

**H. INITIATION OF ANTI-DUMPING INVESTIGATION**

21. On the basis of the duly substantiated written application submitted by the applicant and having reached satisfaction based on the *prima facie* evidence submitted by the applicant concerning the dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, the consequential injury to the domestic industry as a result of the alleged dumping of the product under consideration and the causal link between such injury and the dumped imports, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the AD Rules, the Authority, hereby, initiates an anti-dumping investigation to determine the existence, degree, and effect of the dumping with respect to the product under consideration originating in or exported from the subject countries and to recommend the appropriate amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**I. PROCEDURE**

22. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

**J. SUBMISSION OF INFORMATION**

23. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.

24. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.

25. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification as mentioned in para(23) above.

26. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

27. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at [www.dgtr.gov.in](http://www.dgtr.gov.in) and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

**K. TIME LIMIT**

28. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the

application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.

29. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
30. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 28 above of this Initiation Notification.
31. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.
32. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 28 above. Requests submitted after this time will not be considered

#### **L. SUBMISSION OF INFORMATION ON CONFIDENTIAL BASIS**

33. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
34. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
35. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
36. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
37. The non-confidential version of the information filed by the interested parties is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

#### **M. INSPECTION OF PUBLIC FILE**

41. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

**N. NON-COOPERATION**

42. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority